

>

Title: Regarding problems faced by farmers during claim settlement under Pradhan Mantri Bima Yojna by private insurer.

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम): सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्व का, किसानों का विषय यहां रख रही हूं। हमारे सभी एमपीज के अपने-अपने राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन होता है।

हमने देखा है कि आजकल जो कंपनियां उस पर काम कर रही हैं, वे प्राइवेट कंपनीज हैं। मेरे यहां जो कंपनी है, मैं अपने पार्टिकुलर क्षेत्र की भी बात करना चाहूंगी, उसमें रिलायंस और इफको-टोकियो कंपनी हैं। किसानों का सर्वे होता है, वे बिल्कुल भी किसानों का सर्वे नहीं करती हैं। इन कंपनियों के आने के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ईस्ट इण्डिया कंपनी हमारे भारत में फिर से आई है।

किसान फसल बीमा योजना, आपत्ति के वक्त किसानों की मदद करने के लिए योजना है। हमने जो देखा है और मेरे वक्तव्य से मेरे सारे सांसद भाई भी समर्थन करेंगे, सभी के क्षेत्रों में, जिन्होंने इसका जायजा लिया है, उसमें यही देखने को मिला होगा कि किसानों को बहुत ही कम मुआवजा मिलता है। मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में ये दो कंपनियां काम करती हैं। महाराष्ट्र में भी जो कंपनियां काम करती हैं, उनके सर्वे वाले जो लोग होते हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 16 तालुकाज हैं, तो वहां पर उनके 100 सर्वेयर होते हैं तो मुझे बताइए कि किसानों की इतनी फसल का सर्वे कैसे होगा? ये सारे फेक सर्वे होते हैं। मेरे कहने का मतलब है और मेरी यह मांग भी है कि जो सर्वे इन्होंने किया है, वह ठीक से नहीं किया है। ऐसी कंपनियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और उनको ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए।

महोदय, मैंने वहां पर राज्य सरकार से विनती की है। हमारी राज्य सरकार ने यहां पर एक प्रपोजल भेजा है कि यह जो योजना है, इसको भारतीय कृषि बीमा कंपनी चलाए या इसे स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दें। जब वह सर्वे होगा तो वह सही तरीके से आएगा। अगर सर्वे सही होगा तो किसानों को वहां पर मुआवज़ा मिलेगा। मैं आज देख रही हूं कि किसानों को कोई मुआवज़ा नहीं मिल रहा है। वहां सारे पैसे हड़पने का षडयंत्र चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर किसान को कोई मदद ही नहीं मिल रही है तो कैसे चलेगा? मेरी मांग है कि इस योजना को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार चलाए और किसानों को राहत दे।